जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 91 प्रभात अजमेर, मंगलवार 29 अक्टूबर, 2024 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

क्या आर.बी.आई. के गवर्नर शक्तिकांत दास को एक और एक्सटैंशन मिलेगा

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पत्रिका ग्लोबल फाइनैंस द्वारा भारतीय मॉनिटरी पॉलिसी के लिए शक्तिकांत दास को ''ए प्लस'' रेटिंग दिए जाने से उनका दावा और मजबूत हुआ है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- दिसम्बर 2018 में तत्कालीन आर.बी.आई. गवर्नर उर्जित पटेल के अचानक इस्तीफा देने के बाद, पूर्व वित्त सचिव शक्तिकांत दास को तीन साल के लिए आर.बी.आई. गवर्नर बनाया गया था, सरकार के साथ उनका कार्यकाल एकदम निर्विवादित रहा, इसलिए उन्हें 2021 में 3 साल का एक्सटैंशन दिया गया और इसी आधार पर एक और एक्सटैंशन मिलने की संभावना है।
- उनसे पहले जो दो गवर्नर थे, उर्जित पटेल और रघुराम राजन, उनके सरकार के साथ संबंध विवादों से भरे रहे थे।
- इसी बीच सरकार को तीन और महत्वपूर्ण नियुक्तियां करनी हैं। इनमें से एक है सी.ए.जी., जी.एस. मुर्मू, जिनका कार्यकाल नवम्बर में खत्म हो रहा है। उन्हें एक्सटैंशन नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी नियुक्ति की शर्तों में साफ लिखा है कि रिटायर होने के बाद वे ना एक्सटैंशन ले सकते हैं ना ही कोई नया पद।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार वी.अनंता और सेबी चीफ माधवी पुरी बुच का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है पर उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है। हालांकि, सेबी चीफ के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष, खासकर कांग्रेस आमने-सामने है।

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। क्या रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया (आर.बी.आई.) के गवर्नर को दिसम्बर में तीन वर्षों का तीसरा कार्यकाल मिलेगा? गैर विवादस्पद गवर्नर शक्तिकांत दास के पास वित्तीय क्षेत्र को बेहतरीन तरीके से संभालने तथा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों के कारण शीर्ष पद पर बने रहने की सभी योग्यताएं हैं।

दास के बेदाग ट्रैक रिकॉर्ड को ''ग्लोबल फाइनैंस'' पत्रिका के, 2024 सैंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड ने लगातार दूसरे वर्ष मान्यता दी है। आर.बी.आई. गवर्नर को, जटिल आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत की मॉनिटरी पॉलिसी (मौद्रिक नीति) कुशलतापूर्वक संभालने के लिए रिपोर्ट कार्ड में ''ए प्लस'' रेटिंग दी गई है। यह पुरस्कार वॉशिंगटन डी.सी. में, मुख्य जिम्मेदारियों के आधार पर लगभग 100 केन्द्रीय बैंक गवर्नरों के ग्लोबल असैसमैंट (वैश्विक मूल्यांकन) के आधार पर दिया गया है।

पूर्व वित्त सचिव शक्तिकांत दास को, उरजित पटेल के सरकार के साथ तनाव के बीच दिए गए अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद, दिसम्बर 2018 में तीन साल का पहला कार्यकाल मिला था। फिर तीन साल पहले उनको एक्स्टैंशन दिया गया था। केन्द्र सरकार के साथ उनके मजबूत व स्थिर संबंधों के कारण उनको एक और एक्सटैंशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उनके पूर्ववर्ती, दो आर.बी.आई. गवर्नरों, उरजित पटेल व रघुराम राजन के वित्त मंत्रालय के साथ संबंध अच्छे नहीं थे।

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, दास के साथ-साथ शीघ्र ही तीन और प्रमुख नियुक्तियाँ करनी होंगी। आने वाले महीनों में, केन्द्रीय सरकार को जी.एस. मुर्मू का उत्तराधिकारी नियुक्त करना होगा,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अडानी और सेबी चीफ प्र.मंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं'

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। सोमवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अडानी और सेबी चीफ माधवी पुरी बुच मोदी सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि यदि उनपर या उनका सहयोग कर रहे किसी भी व्यक्ति पर हमला हुआ तो सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

राहुल गांधी ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 4 मिनट 39 सेकेंड का एक वीडियो क्लिप (टीजर) पोस्ट किया। राहुल ने कहा, संस्थागत पतन ने अब भाई-भतीजावाद के अधिक खतरनाक स्वरूप अडानी बचाओ सिंडिकेट को जन्म दिया है। मौजूदा सरकार अब केवल एकाधिकार को बढ़ावा नहीं दे रही है, बल्कि सक्रिय रूप से देश की संपत्ति को कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित कर रही है।

- राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बुच अडानी के हितों की रक्षा के लिए सिस्टम में हेर-फेर कर रही है और केन्द्र सरकार चुप है।

उन्होंने कहा कि माधबी बुच कांड जितना सोचा गया था, उससे कहीं अधिक गहरा है। हो सकता है कि खुदरा निवेशकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही बुच अडानी के हितों की रक्षा के लिए सिस्टम में हेरफेर कर रही हों।

'एक प्रदेश में कितने सांसद हों, यह जनगणना के आकड़े निर्धारित करेंगे?

ऐसे मुद्दों पर निर्णय के लिये सरकार एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- एक और मुद्दा कांग्रेस बार-बार उठा रही है, कि क्या जनगणना में जातिगत सर्वे ही होगा। इस प्रश्न पर भी कांग्रेस सर्वदलीय बैठक में निर्णय कराना चाहती है।
- सैन्सस कमिश्नर का कार्यकाल बढ़ाने की घोषणा के बाद, यह चर्चा जोरों पर है कि शीघ्र ही सरकार सैन्सस (जनगणना) करायेगी।

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। कांग्रेस ने आज बहु-प्रतीक्षित जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर प्रश्नों की बौछार की। कांग्रेस ने माँग की कि सरकार जनगणना से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए सर्वदलीय मीटिंग बुलायें।

कांग्रेस की यह माँग उन मीडिया-रिपोर्टों के बाद आई है, जिनमें दावा किया गया था कि सरकार द्वारा जनगणना अगले वर्ष कराये जाने के सम्भावना है।

कांग्रेस महासचिव तथा मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, ''रजिस्ट्रार जनरल तथा जनगणना आयुक्त के कार्यकाल में वृद्धि की अधिसूचना अभी-अभी जारी हुई है। इसका अर्थ यह निकलता है कि अति-विलम्बित जनगणना, जो 2021 में होनी थी, आखिरकार शीघ्र ही कराई जायेगी। लेकिन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति अभी भी कतई स्पष्ट नहीं है।''

रमेश ने पूछा है कि क्या ''नई जनगणना'' में अनुसूचित जातियों (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) की गणना, जो 1951 से बाद से प्रत्येक जनगणना में की जाती रही है, के अतिरिक्त देश की सभी जातियों की विस्तृत गणना शामिल होगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार, इस प्रकार की जातिगत जनगणना कराना संघीय सरकार का अनन्य दायित्व है।

उन्होंने पूछा, ''क्या इस जनगणना का उपयोग लोकसभा में प्रत्येक राज्य की संदस्य संख्या के निर्धारण के लिये किया जायेगा, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में जरूरी बताया गया है (यह अनुच्छेद कहता है कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तथा इसके परिणामों का प्रकाशन ऐसे किसी भी पुनर्गठन का आधार होगा ? क्या इस कार्य से उन राज्यों को नुकसान होगा, जो परिवार-नियोजन के मामले में आगे रहे हैं?'' उन्होंने कहा, ''सर्वाधिक उपयुक्त यह रहेगा कि इन दो प्रमुख मुद्दों पर स्पष्ट स्थिति लाने के लिये एक सर्वदलीय मीटिंग जल्दी ही बुलाई जाये।''

महाराष्ट्र एवं झारखंड के चुनावों में बड़ी समानता है ''परिवारवाद''

परिवारवाद को लेकर कांग्रेस की आलोचना करने वाली भाजपा भी इससे अछूती नहीं है

-श्रीनन्द झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- झारखंड में भाजपा ने अर्जुन मुंडा की पत्नी, चंपई सोरेन के बेटे, रघुवर दास की पुत्रवधु सहित कई नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिए हैं।

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। महाराष्ट्र एवं झारखंड के आसन्न विधानसभा चुनावों में एक बात समान है, वो है परिवारवाद। सभी राजनैतिक दलों ने इन चुनावों में अच्छी खासी संख्या में राजनैतिक उत्तराधिकारी खड़े किए हैं। भाजपा, जो परिवारवादी राजनीति के खिलाफ अक्सर शोर मचाती रहती है,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भतीजे के खिलाफ भतीजा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन बंद होने के एक दिन पहले सोमवार को, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री तथा एन.सी.पी. प्रमुख अजित पवार ने अपना नामांकन पत्र बारामती से भर दिया तथा अब वे इस सीट पर अपने भतीजे तथा शरद पवार के पौत्र युगेन्द्र पवार (एन.सी.पी.-एस.पी. उम्मीदवार) का सामना करेंगे।

- शरद पवार के बारामती से अपने भतीजे अजित पवार के सामने उनके ही भतीजे युगेन्द्र पवार को मैदान में उतारा है।

विदित ही है कि अजित, जिन्होंने शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिये पार्टी तोड़ दी थी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शिव सेना उम्मीदवार के रूप में थाने जिले की कोप्री-पचपाखाड़ी सीट से अपना नामांकन भर दिया है।

सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रतिद्वंदी शरद पवार ने सोमवार को कहा कि महविकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) महाराष्ट्र में जन-

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'नड्डा और मैं भाई हैं, क्योंकि, एक ही ''आइलियोलॉजिकल परिवार'' के सदस्य हैं'

आर.एस.एस. के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने मथुरा में आयोजित संघ के कार्यकारी मण्डल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रैंस में कहा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- होसबाले ने इस संदर्भ में यह भी कहा कि भाजपाध्यक्ष जे.पी. नड्डा व आर.एस.एस. के बीच मतभेद की बात को कपोल कल्पित है, उन्होंने यह भी कहा कि नड्डा की लोकसभा चुनाव के पहले दी गई बहुचर्चित टिप्पणी के बाद, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद वे नड्डा के घर गये थे तथा भोजन किया था।
- होसबाले ने यह भी कहा कि आर.एस.एस. योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन करती है कि ''हिन्दू बंटेंगे, तो कटेंगे।''

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने हिन्दू एकता के महत्व पर जोर देते हुए, भाजपा के साथ किसी प्रकार मतभेद न होने की फिर से पुष्टि की। वे मथुरा के परखन गाँव में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने अपने वक्तव्य में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ के नारे ''बँटेंगे तो कटेंगे'' का समर्थन किया, उन्होंने जोर देते हुए, इस नारे को एकता का आव्हान बताया।

होसबाले ने भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के साथ अपने सम्बन्ध का जिक्र करते हुए, उन्हें समान वैचारिक परिवार का अपना भाई बताया।

भाजपा अध्यक्ष के साथ किसी प्रकार की दरार का खंडन करते हुए, होसबाले ने कहा कि चुनाव तथा अन्य मामलों में संघ से पार्टी की स्वतन्त्रता के बारे में आम चुनावों से पहले की भाजपा अध्यक्ष की टिप्पणी के बाद तो उन्होंने नड्डा के निवास पर भोजन किया था। उन्होंने कहा कि उस समय तक लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए थे।

मथुरा में संघ के कार्यकारी मंडल (केन्द्रीय कार्यकारी) की मीटिंग के अन्तिम दिन, होसबाले कई मुद्दों पर बोले थे। इनमें ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म के नियमन, न कि नियन्त्रण, की आवश्यकता भी शामिल थी। उन्होंने कहा था कि इसके लिये फिल्म सेंसर बोर्ड जैसी कोई व्यवस्था की जा सकती है।

योगी आदित्यनाथ के ''बँटेंगे तो कटेंगे'' नारे के बारे में पूछे गये एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, होसबाले ने हिन्दू एकता के रेखांकित संदेश तथा जाति, रंग या मतों पर आधारित विभाजन के खतरे विस्तार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रियंका ने वायनाड में मदर टैरेसा से मुलाकात का किस्सा सुनाया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। वायनाड में अपने चुनाव प्रचार के पहले दिन प्रियंका गांधी ने मदर टैरेसा के साथ अपनी एक मुलाकात का उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि उनके पिता राजीव गांधी हत्या के कुछ माह बाद मदर टैरेसा उनके घर आई थी। मदर ने प्रियंका से कहा था कि वे दीन दुखियारों के लिए काम करें। इसके बाद प्रियंका ने मदर टैरेसा के संगठन में जाकर काम किया।

- प्रियंका ने बताया कि उनके पिता की हत्या के कुछ माह बाद मदर टैरेसा उनके घर आईं थीं और उन्हें दीन दुखियों के लिए काम करने की प्रेरणा दी थी।

प्रियंका ने बताया, उस समय मैं 17 साल की थी। मेरे पिता का निधन हुए 6-7 माह ही हुए थे। मुझे बुखार था तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। फिर वो खुद मेरे कमरे में आई। अपना हाथ मेरे माथे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र चुनाव की खींचतान में कांग्रेस ने भाजपा व मोदी सरकार पर नया आरोप लगाया

कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार महाराष्ट्र के हितों की बलि दे रही है और प्र.मंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में लगने वाले कई उद्योग व सैंटर गुजरात भेज दिए हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में जिस टाटा एयरबस सी-295 फैसिलिटी का उद्‌घाटन किया है वह नागपुर में लगने वाली थी।
- कांग्रेस ने कहा, इससे पहले वेदांत फॉक्सकॉन चिप फैक्टरी, इंटरनैशनल फायनैंशियल सर्विसेज़ सैंटर, डायमंड ट्रेड सैंटर, ड्रग पार्क भी महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात भेज दिए गए।
- महाराष्ट्र के महत्व को देखते हुए विधानसभा चुनावों में भारी तनाव है, यहाँ हरेक दल आरोपों की राजनीति कर रहा है।

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि टाटा एयरबस सी-295 के जिस निर्माण संयंत्र का वडोदरा में उद्‌घाटन हुआ है वो पहले नागपुर में लगने वाला था और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इशारे पर केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने महाराष्ट्र के हितों को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री व उनके सहयोगियों को इस धोखे का माकूल जवाब देगी।

प्रधानमंत्री मोदी व स्पेन के प्रधानमंत्री पैड्रो सांचेज़ द्वारा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड-एयरबस फैसिलिटी का उद्‌घाटन किया गया, जिसमें सी-295 सैन्य विमान बनाए जाएंगे। इस उद्‌घाटन के बाद कांग्रेस ने यह आरोप लगाया। टाटा एयरबस फैसिलिट प्राइवेट सैक्टर का पहला संयंत्र है, जहाँ सैन्य विमान एसैम्बल किए जाएंगे।

रमेश ने कहा, आज नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने वडोदरा में टाटा-एयरबस सी-295 एयरक्राफ्ट फैसिलिटी जारी कर उद्‌घाटन किया। यह वही प्रोजैक्ट है जो नागपुर में लगने वाला था, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले उसे गुजरात भेज दिया गया।

रमेश ने कहा, यह एकमात्र घटना नहीं है। नॉन बायोलॉज़िकल प्रधानमंत्री के निर्देश पर केन्द्र सरकार और महायुति सरकार ने साजिश रच के महाराष्ट्र के हितों की तिलांजलि दे दी है।

पूर्व की घटनाओं को उदाहरण देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा इन्टरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज़ सैंटर भी गुजरात में लगाया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मुम्बई में यह सैंटर लगाने के प्रयास शुरु किये थे। बांद्रा कुर्ला परिसर में आई.एफ.एस.सी. के लिए अलग से जमीन रख दी गई थी, पर उस प्रयास को भारी हानि पहुंचाई गई। इससे मुम्बई को दो लाख नौकरियों का नुकसान हुआ।

रमेश ने कहा कि भारत के डायमंड उद्योग को विकसित करने के लिए मुम्बई और सूरत ने कई दशकों से साथ मिलकर काम किया है। सूरत में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)